भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3616
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: जीआई-टैग वाली कंधमाल हल्दी की खेती और निर्यात को बढ़ावा देना

3616. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी विशिष्ट गुणवत्ता और विरासत के लिए विख्यात जीआई-टैग वाली कंधमाल हल्दी की खेती और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कोई कदम उठाए हैं;

(ख) सरकार कंधमाल हल्दी से जुड़े बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करेगी और इस मान्यता से क्षेत्र के किसानों को कितना लाभ होगा;

(ग) क्या सरकार का प्रशिक्षण और कौशल विकास के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनी बाजार उपस्थिति को बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग सहित कंधमाल हल्दी के मूल्य संवर्धन हेतु कोई पहल करने का विचार है; और

(घ) क्या मसाला फसलों और जैविक खेती के विकास के लिए सरकारी योजनाओं में कंधमाल हल्दी को शामिल करने की कोई योजना है जिससे इस क्षेत्र में किसानों के लिए सतत् वृद्धि और लाभप्रदता सुनिश्चित हो सके?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार ने कंधमाल हल्दी की बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए ओडिशा राज्य के मसाला मिशन के माध्यम से जीआई (भौगोलिक संकेत) टैग वाली कंधमाल हल्दी की खेती और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कंधमाल हल्दी की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक जैसे प्रचार कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये प्रयास यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बनाने पर केंद्रित हैं।

मसाला बोर्ड कंधमाल हल्दी सहित ओडिशा के मसालों के फसलोपरांत सुधार और निर्यात संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना "निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवाचार और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता" (एसपीआईसीडी) को कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पोटांगी, ओडिशा में मसालों पर आईसीएआर-अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) इस क्षेत्र में जीआई-टैग वाले कंधमाल हल्दी किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को जैविक उत्पादन और इसके मूल्य संवर्धन पर निरंतर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ताकि किसान अपने जैविक उत्पाद का निर्यात भी कर सकें।

ओडिशा सरकार कंधमाल हल्दी से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसे स्थानीय उत्पादकों के माध्यम से जीआई टैग वाले उत्पाद के रूप में मान्यता दी गई है, जो कंधमाल हल्दी की ब्रांडिंग के लिए गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एपीडा और कंधमाल एपेक्स स्पाइसेस एसोसिएशन फॉर मार्केटिंग के सहयोग से किसानों और उत्पादक समूहों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। ये पहल किसानों को जीआई के मूल्य और कानूनी निहितार्थों के बारे में शिक्षित करती हैं ताकि अनुपालन और सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।

(ग) : सरकार ने निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने हेतु क्लीनिंग, ड्राइंग, पाउडरिंग और पैकेजिंग के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के माध्यम से कंधमाल हल्दी के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। एपीडा अत्याधुनिक समाधानों सहित खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहयोग कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मान्यता बढ़ाने के लिए इंडो-जर्मन कृषि बाजार विकास परियोजना जैसी पहलों सहित ब्रांडिंग कार्यनीतियों के माध्यम से निर्यात संवर्धन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा, प्रमाणन और निर्यात आवश्यकताओं पर कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन के माध्यम से एपीडा से जुड़े कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।

(घ) : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एमआईडीएच के अंतर्गत सुपारी और मसाला विकास निदेशालय (डीएसडी) के माध्यम से कंधमाल हल्दी सहित हल्दी की खेती को एफपीओ के माध्यम से क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग द्वारा संवर्धन कर रहा है ताकि इस क्षेत्र में जैविक खेती के साथ सतत विकास और किसानों को लाभ सुनिश्चित किया जा सके।